भेड़ और बकरियों के उत्पादों का मूल्यसंवर्धन

प्रेम पाल रोहिल्ला[1] और **बाबू लाल जांगिड़**[2]

“ विश्व में भेड़ों और बकरियों की वर्तमान संख्या क्रमशः लगभग 1 अरब और 1.3 अरब है। एशिया में विश्व की 40.38 प्रतिशत भेड़ें तथा 63.78 प्रतिशत बकरियां पाई जाती हैं, जबकि भारत में विश्व की 4.54 प्रतिशत भेड़ें और 16.3 प्रतिशत बकरियां (20वीं पशुधन गणना) हैं। भेड़ एवं बकरी पालन छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों के लिए आय, रोजगार तथा पोषण का प्रमुख आधार है। वर्ष 2010-2020 के दौरान भारत से प्रतिवर्ष लगभग 9,000-11,500 मीट्रिक टन भेड़ एवं बकरी के मांस का निर्यात हुआ, जिससे 44-85 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई। देश में प्रतिवर्ष लगभग 19 प्रतिशत भेड़ों तथा 38 प्रतिशत बकरियों का वध होता है। वर्तमान में भारत में भेड़ एवं बकरी के मांस की खपत 1 मिलियन टन से अधिक है तथा इसमें 2.3-10.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही है। बढ़ती मांग को देखते हुए राजस्थान की भेड़ एवं बकरी नस्लों से मूल्यवर्धित उत्पाद विकसित कर पशुपालकों की आय बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं। ”

राजस्थान अपनी उत्कृष्ट भेड़ एवं बकरी नस्लों और विशाल पशुधन संपदा के कारण मांस आधारित मूल्यवर्धित उत्पादों के विकास की अपार संभावनाएं रखता है। बदलती उपभोक्ता मांग और आधुनिक उत्पादन प्रणालियों के अनुरूप इन संसाधनों का बेहतर उपयोग समय की आवश्यकता है।

छोटे जुगाली करने वाले पशु मांस के प्रमुख स्रोत हैं, फिर भी राजस्थान में इनकी व्यावसायिक क्षमता का अपेक्षित स्तर पर उपयोग नहीं हो पाया है। 20वीं पशुधन गणना (वर्ष 2020) के अनुसार राज्य में लगभग 79 लाख भेड़ें तथा 208.4 लाख बकरियां हैं।

प्रमुख बकरी नस्लों में मारवाड़ी, सिरोही, जाखराना और बरबरी, जबकि प्रमुख भेड़ नस्लों में चोकला, मारवाड़ी, जैसलमेरी और मगरा शामिल हैं।

हालांकि चरागाहों की कमी, कृषि क्षेत्र का विस्तार तथा पारंपरिक व्यापक चराई प्रणाली इन पशुओं के वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक पालन में प्रमुख बाधाएं हैं। इसलिए अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता वाले मांस के लिए पारंपरिक प्रणाली के स्थान पर अर्धसघन एवं सघन पालन प्रणालियों को बढ़ावा देना आवश्यक है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के बाद बदलते वैश्विक बाजार, उपभोक्ताओं

विपणन चुनौतियों का समाधान

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़-बकरियों की खरीद-बिक्री अभी भी असंगठित व्यवस्था पर आधारित है। चरवाहे गांवों से पशु खरीदकर बिचौलियों को बेचते हैं, जो उन्हें महानगरों तक पहुंचाते हैं। सामान्यतः 18-20 कि.ग्रा. वजन वाले वयस्क अथवा कम उत्पादक पशु 4,000-4,500 रुपये प्रति पशु, जबकि 22-25 कि.ग्रा. वजन वाले युवा मेमने 7,000-7,500 रुपये प्रति पशु में बिकते हैं। इस व्यवस्था में वास्तविक लाभ बिचौलियों को मिलता है, जबकि पशुपालकों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। राजस्थान में संगठित वधशालाओं और वैज्ञानिक विपणन अवसंरचना का अभाव होने के कारण बड़ी संख्या में भेड़-बकरियों को गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भेजा जाता है। वहीं, राज्य के कुछ प्रगतिशील पशुपालकों ने व्यावसायिक भेड़-बकरी पालन अपनाकर मांस उत्पादन तथा त्यौहारों के दौरान जीवित पशुओं की बिक्री से बेहतर आय प्राप्त की है। यदि ऐसे प्रदर्शन फार्म राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी विकसित किए जाएं, तो व्यावसायिक मांस उत्पादन को उल्लेखनीय बढ़ावा मिल सकता है। वर्तमान में जीवित पशुओं के विपणन, स्वास्थ्य परीक्षण, स्वच्छ वध, मांस गुणवत्ता परीक्षण तथा संगठित मंडियों की कमी प्रमुख चुनौतियां हैं। टिकाऊ और लाभकारी मांस उत्पादन के लिए वैज्ञानिक पालन, पर्याप्त चारा, आधुनिक प्रसंस्करण, स्वच्छ वधशालाएं, प्रभावी विपणन, उपउत्पादों का बेहतर उपयोग तथा मूल्यवर्धित उत्पादों के विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है

[1]प्रधान वैज्ञानिक (पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन); [2]प्रधान वैज्ञानिक (कृषि प्रसार), भाकृअनुप-कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, क्षेत्र-द्वितीय, काजरी कैम्पस, जोधपुर-342005 (राजस्थान)

चारा प्रबंधन

उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ चारा प्रबंधन और पोषण पर निरंतर ध्यान देना आवश्यक है। आधुनिक भेड़ एवं बकरी पालन प्रणालियों में लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी उपयोग रणनीतियां अपनानी होंगी, जो उत्पादन के साथ बाजार की मांग को भी पूरा करें। वर्तमान में उपभोक्ता केवल मटन और सेवन ही नहीं, बल्कि उच्च गुणवत्ता, विविधता और सुविधाजनक मूल्यवर्धित उत्पादों की भी अपेक्षा करते हैं। मांस की गुणवत्ता नस्ल, चारा, प्रबंधन, आयु, लिंग, वध एवं प्रसंस्करण जैसी अनेक बातों पर निर्भर करती है। विशेष रूप से शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में चारे की कमी व्यावसायिक मांस उत्पादन की प्रमुख चुनौती है, जिस पर प्राथमिकता से कार्य करने की आवश्यकता है।

मारवाड़ी नस्ल की भेड़

की गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं और बढ़ती मांग को देखते हुए राजस्थान की भेड़ एवं बकरी नस्लों से मूल्यवर्धित मांस उत्पादों का विकास पशुपालकों की आय बढ़ाने और ग्रामीण उद्यमिता को सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

भारत और विदेशों में भेड़ एवं बकरी के मांस से अनेक मूल्यवर्धित उत्पाद विकसित किए गए हैं। विशेष रूप से वृद्ध पशुओं के कठोर मांस को पिसे हुए या पुनर्गठित (रीस्ट्रक्चर्ड) उत्पादों के रूप में प्रसंस्करित कर उसकी गुणवत्ता और स्वीकार्यता बढ़ाई जाती है। प्रमुख मूल्यवर्धित उत्पादों में कबाब, मीटबॉल, पैटी, अचार, बकरी के मांस का हैम, कीमा, टिक्का, क्रोकेट, मध्यम नमी वाले चंक्स, कम वसा वाले उत्पाद, मीट ब्लॉक, नगेट्स, मटन हैम तथा सॉसेज शामिल हैं।

भारतीय बाजारों में उपलब्ध भेड़ एवं बकरी का अधिकांश मांस बूढ़े पशुओं अथवा 6-12 माह आयु के नर मेमनों से प्राप्त होता है। झाड़ीदार वनस्पति पर आधारित पारंपरिक पालन के कारण इनका बाजार वजन प्रायः 15-16 कि.ग्रा. ही होता है, जिससे ड्रेसिंग प्रतिशत, मांस-हड्डी अनुपात तथा मांस की गुणवत्ता प्रभावित होती है। शोधों से स्पष्ट हुआ है कि शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में पूरक आहार देने से अंतिम वजन और मांस की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है।

अर्धसघन प्रणाली में 8-10 घंटे प्राकृतिक चराई के साथ एक दिन छोड़कर प्रति बच्चे 200 ग्राम सांद्र आहार देने से बकरी के मेमनों की वृद्धि दर पारंपरिक प्रणाली की तुलना में 55-57 प्रतिशत अधिक पाई गई। इससे पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर रहता है तथा प्रति बच्चे लगभग 6,250 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

इसी प्रकार, दो माह आयु के मारवाड़ी मेमनों को 6-8 घंटे चराई के साथ संतुलित पूरक आहार देने पर वे केवल 6 माह में लगभग 30 कि.ग्रा. वजन प्राप्त कर लेते हैं। इस तकनीक से पालन अवधि 12 माह से घटकर 6 माह रह जाती है तथा प्रति मेमना लगभग 8,250 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त होने के साथ मृत्यु दर और पालन लागत में भी कमी आती है।

मांस की बढ़ती मांग को देखते हुए भेड़ एवं बकरी पालन को पारंपरिक से व्यावसायिक मॉडल की ओर ले जाना आवश्यक है। सघन एवं अर्ध सघन पालन, जीवित भार आधारित विपणन, बिचौलियों की भूमिका में कमी तथा ग्रामीण मांस उत्पादन केंद्रों को बढ़ावा देकर पशुपालकों की आय बढ़ाई जा सकती है। साथ ही, प्रसंस्करित एवं मूल्यवर्धित मांस उत्पादों का विकास, आधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रसार तथा सरकार, सहकारी संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों के समन्वित प्रयास राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में छोटे पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

वैज्ञानिक प्रबंधन से स्वस्थ मेमने